अमरजीत की किस्मत में आई खतरनाक मौत- कैंटर ने मारी टक्कर, कैंपर के अंदर ही फंसा; राहगीरों ने खींचकर निकाला शव

गुरुग्राम ।हरियाणा के गुरुग्राम स्थित फर्रुखनगर थाना क्षेत्र में सुल्तानपुर-गुरुग्राम रोड पर इंडियन गैस एजेंसी के सामने 16 मई की रात करीब 10.15 बजे तेज रफ्तार कैंटर ने कैंपर गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में कैंपर चालक को गंभीर चोटें लगने के कारण मौत हो गई। मृत युवक के भाई विनोद कुमार की शिकायत पर पुलिस ने फर्रुखनगर थाने में कैंटर चालक धर्मेंद्र के खिलाफ सड़क हादसे में मौत संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है। मृतक की पहचान भिवानी के रिवाड़ी खेड़ा गांव निवासी अमरजीत (38) के रूप में हुई है। वह वर्तमान में परिवार के साथ सुल्तानपुर गांव में किराये पर रहता था।

बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

● वर्ष: 24 ● अंक: 193 ● नई दिल्ली ● सोमवार 18 मई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

ऑन-स्क्रीन मार्किंग के बीच सीबीएसई का बड़ा फैसला, बोर्ड ने पुनर्मूल्यांकन शुल्क घटाकर 100 रुपये किया

नई दिल्ली । ऑन-स्क्रीन मार्किंग को लेकर चल रही बहस के बीच सीबीएसई ने एक अहम निर्णय लिया है। बोर्ड ने छात्रों के हित में कदम उठाते हुए पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिका सत्यापन की फीस में भारी कमी की है, जिससे अब यह प्रक्रिया पहले से अधिक आसान और किफायती हो गई है। सचिव संजय कुमार ने बताया कि अब किसी छात्र से उत्तर पुस्तिका देखने के लिए 100 रुपये शुल्क लिया जाएगा, उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन के लिए 100 रुपये और किसी विशेष प्रश्न के उत्तर की पुनः जांच के लिए 25 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जांच प्रक्रिया में छात्र के अंक बढ़ते हैं या संशोधित होते हैं, तो उससे लिया गया पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। सचिव संजय कुमार ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई के लिए सभी छात्रों का हित सबसे ऊपर है। उन्होंने बताया कि किसी भी छात्र को यह

महसूस नहीं होना चाहिए कि उसके वास्तविक प्रदर्शन के अनुसार उसे कम अंक मिले हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था पहले से ही सीबीएसई में मौजूद है और अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी अंकों की गणना पूरी तरह सही और सटीक हो। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अगर कोई छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका देखना या उसका सत्यापन कराना चाहता है, तो इसके लिए अब पहले से कम शुल्क लिया जाएगा, ताकि यह प्रक्रिया छात्रों के लिए आसान और पारदर्शी बन सके। इस प्रक्रिया के पहले चरण में प्रति विषय उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई कॉपी प्राप्त करने के लिए 700 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया था। इसके बाद दूसरे चरण में त्रुटि सत्यापन के लिए 500 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका और पुनर्मूल्यांकन के लिए 100 रुपये प्रति प्रश्न शुल्क निर्धारित किया गया था।

स्कैन कॉपी पाने का क्या है पूरा तरीका?

पहला चरण मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन करना है। कक्षा 12वीं के लिए फीस और समय-सारणी पहले से तय की गई है।आवेदन केवल छात्र को खुद ऑनलाइन करना होगा, साइबर कैफे या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा आवेदन करने से बचने की सलाह दी गई है। स्कैन कॉपी छात्र की लॉगिन आईडी पर उपलब्ध कराई जाएगी, जहां से उसे डाउनलोड किया जा सकेगा। कॉपी ÷पहले आओ, पहले पाओ÷ के आधार पर मिलेगी, यानी जो पहले आवेदन करेगा उसे पहले कॉपी मिलेगी। छात्र एक या अधिक विषयों के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन आवेदन एक ही बार में करना होगा। अगर छात्र अंकों से असंतुष्ट है, तो आगे सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है।

दिल्ली-एनसीआर में भीषण हीटवेव का प्रकोप- पारा 45 डिग्री तक पहुंचने के आसार, आईएमडी का अलर्ट

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में आने वाले दिनों में भीषण गर्मी लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 22 मई तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में लू से लेकर गंभीर लू (सीवियर हीटवेव) की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में अगले तीन दिनों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। रविवार को अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। इसके बाद आसमान साफ रहने से गर्मी और बढ़ेगी और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। रात के समय भी गर्म हवाएं चलने और तापमान अधिक रहने से लोगों को राहत मिलने की संभावना कम है। मौसम विभाग के अनुसार, मैदानी इलाकों में जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाए और सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस या अधिक ऊपर चला जाए, तो उसे हीटवेव माना जाता है। यदि तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पहुंच जाए, तो उसे सीधे लू की स्थिति माना जाता है, चाहे सामान्य तापमान से अंतर कितना भी हो। तेज गर्मी और लू के कारण डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और बाहर काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल उत्तर और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना बेहद कम है। लोगों को सतर्क रहने और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है।

संजय सिंह का केंद्र पर हमला, बोले- पेपर लीक ने 22 लाख युवाओं का भविष्य किया बर्बाद, जिम्मेदार कौन?

नई दिल्ली । आप सांसद संजय सिंह ने देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं ने 22 लाख से यादा युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है, लेकिन अब तक किसी बड़े जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई. संजय सिंह ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अब तक 93 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं. जिनमें यादातर बीजेपी शासित रायों में हुए.

पेपर रद्द के बाद बच्चे कर रही आत्महत्या- संजय सिंह

संजय सिंह ने कहा कि इन घटनाओं से लाखों छात्र मानसिक तनाव और निराशा का सामना कर रहे हैं. इसी दौरान उन्होंने अंशिका पांडे नाम की

एक छात्रा का जिक्र किया, जो तीसरी बार परीक्षा दे रही थी. पिछली बार वह सिर्फ चार अंकों से चयन से चूक गई थी. इस बार उसे पूरी उम्मीद थी कि उसका चयन हो जाएगा, लेकिन परीक्षा रद्द होने के बाद उसने आत्महत्या कर ली. संजय सिंह ने कहा कि यह केवल आत्महत्या नहीं, बल्कि व्यवस्था की विफलता है. जिसने एक छात्रा की जिंदगी छीन ली.

पेपर लीक का लगातार बढ़ रहा कारोबार-संजय सिंह

आप सांसद ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए कानून जरूर बनाया है, लेकिन वह जमीन पर असरदार साबित नहीं हो रहा. यही वजह है कि पेपर लीक का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर देश के युवाओं के टूटते सपनों और उनकी मौतों का जिम्मेदार कौन है. संजय सिंह ने मांग की है कि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करें और ऐसी व्यवस्था बनाए, जिससे युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह सके.

पीएम मोदी की अपील के बाद डीएमआरसी का फैसला, हर सोमवार को चलेंगी छह अतिरिक्त ट्रेनें, बढ़ेंगे 24 फेरे

नई दिल्ली । पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने की अपील के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने 18 मई से प्रत्येक सोमवार को छह अतिरिक्त ट्रेनों के जरिए 24 अतिरिक्त ट्रेन फेरे चलाने की घोषणा की है। जरूरत पड़ने पर अन्य दिनों में भी अतिरिक्त सेवाएं संचालित की जाएंगी। डीएमआरसी के अनुसार, मौजूदा परिस्थितियों में सड़क परिवहन से मेट्रो की ओर यात्रियों का रुझान बढ़ सकता है। इसे देखते हुए स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, टिकट काउंटरों की संख्या बढ़ाने, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और बैगेज स्कैनर सक्रिय करने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने की तैयारी की गई है। डीएमआरसी ने कहा कि उसका विस्तृत नेटवर्क रेलवे स्टेशनों, आईएसबीटी, एयरपोर्ट, नमो भारत कॉरिडोर और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इससे निजी वाहनों और पेट्रोलियम आधारित परिवहन पर निर्भरता कम करने में मदद मिल रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए 160 मेट्रो स्टेशनों पर

लास्ट माइल कनेक्टिविटी नेटवर्क विकसित किया गया है, जिसमें ई-रिक्शा, ई-ऑटो, बाइक टैक्सी और साइकिल सेवाएं शामिल हैं। डीएमआरसी का दावा है कि इससे रोज करीब एक लाख यात्री लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा 126 मेट्रो स्टेशनों पर पार्क एंड राइड सुविधा भी उपलब्ध है। डीएमआरसी ने डिजिटल टिकटिंग को भी बढ़ावा दिया है। यात्री अब क्यूआर टिकट, एनसीएमसी कार्ड, व्हाट्सऐप टिकटिंग और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं।

दिल्ली में फिर लौटेंगे वर्क फॉम होम के दिन - सरकार की निजी कंपनियों से अपील- सप्ताह में 2 दिन घर से कराएं काम

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच ईंधन बचाने के प्रयासों में सहयोग के लिए निजी कंपनियों और प्रतिष्ठानों को दो दिन की वर्क-फ्रॉम-होम नीति अपनाने, कार्यालय के समय में बदलाव करने और कर्मचारियों से कार पूलिंग और सार्वजनिक परिवहन का लाभ उठाने का आग्रह किया है। दिल्ली श्रम विभाग द्वारा जारी परामर्श में अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों, बिजली, पानी, स्वच्छता और संबंधित नगरपालिका सेवाओं जैसी आवश्यक, आपातकालीन सेवाओं में शामिल निजी संस्थाओं को शामिल नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस सप्ताह की शुरुआत में 90-दिवसीय मेरा भारत, मेरा योगदान ईंधन बचत अभियान शुरू किया जिसमें दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए दो दिन घर से काम करने और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा था कि संसाधनों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल के संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील के जवाब में निजी क्षेत्र को भी ईंधन-बचत पहल का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। श्रम विभाग ने रविवार को जारी परामर्श में कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी जैसे ईंधनों की बचत करना तथा उनका सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित

करना आवश्यक है। इसमें कहा गया है कि राजधानी में रोजाना वाहनों द्वारा होने वाली ईंधन खपत में दफ्तर आने-जाने का बड़ा योगदान होता है। परामर्श में कहा गया कि वर्क-फ्रॉम-होम व्यवस्था अपनाकर ईंधन की खपत का बड़ा हिस्सा कम किया जा सकता है। कोविड-19 महामारी और चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना (ग्रैप) प्रतिबंधों के दौरान इसकी संचालन संबंधी व्यवहार्यता भी साबित हो चुकी है। परामर्श में कहा गया, राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन बचत के प्रयासों में योगदान देने के लिए दिल्ली के सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों, कारखानों, दुकानों और आईटी और आईटीईएस (आईटी संबद्ध सेवाएं) क्षेत्र समेत वाणिज्यिक संस्थानों के नियोक्ताओं को सप्ताह में कम से कम दो दिन वर्क-फ्रॉम-होम लागू करने के लिए जोरदार तरीके से प्रोत्साहित किया गया है। इस परामर्श में सड़कों पर व्यस्त समय के दौरान वाहनों की भीड़ को कम करने के लिए अलग-अलग कार्य घंटों को लागू करने, कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन, कार-पूलिंग या गैर-मोटर चालित आवागमन के साधनों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने का भी सुझाव दिया गया। परामर्श में यह भी सलाह दी गई कि यात्रा खर्च घटाने के लिए प्रत्यक्ष बैठकों को डिजिटल या ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जाए गैर-जरूरी यात्राओं में आधिकारिक वाहनों का कम से कम इस्तेमाल हो और निर्बाध वर्क-फ्रॉम-होम व्यवस्था के लिए पर्याप्त आईटी ढांचा उपलब्ध कराया जाए। निजी क्षेत्र को भी आवागमन के विकल्प चुनकर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की खपत को कम करने और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारतीय निर्मित उत्पादों को खरीदने का संकल्प लेने की सलाह दी गई है।

'होम मिनिस्टर'

हमारे यहां घरों-परिवारों पर जब कभी वित्तीय संकट आते हैं तो गृहलक्ष्मी ही इसे संभालती है तथा संकट मोचक की भूमिका निभाती है। क्योंकि महिलाएं घर बहुत अच्छी तरह से चलाना जानती हैं तथा रसोई व घर के अन्य खर्चों पर कंट्रोल करती हैं, इसीलिए उन्हें घरों में 'होम मिनिस्टर' भी कह दिया जाता है। मेरा मानना है कि संकट के समय भारत को मजबूत बनाने में महिलाओं की भूमिका और भी अहम बन जाती है ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'बचत और आत्मनिर्भरता' की अपील का महत्व और भी बढ़ जाता है। ईरान-इजराइल-अमेरिका युद्ध के चलते भारत पैट्रोल व गैस खपत को लेकर प्रभावित हुआ है। पीएम मोदी ने कठिन हालात को पढ़ लिया है तभी तो उन्होंने खर्च कंट्रोल करने की अपील की है। भारत एक ऐसा देश है जहां महिलाओं ने हर दौर में परिवार, समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज जब दुनिया आर्थिक चुनौतियों, महंगाई, प्राकृतिक संकटों और संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं का सामना कर रही है, तब प्रधानमंत्री ने देशवासियों से जीवन के हर क्षेत्र में बचत, आत्मनिर्भरता और जिम्मेदार जीवनशैली अपनाने की अपील की है। इस अभियान को सफल बनाने में महिलाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे घर की व्यवस्था, संसाधनों के उपयोग और परिवार के संस्कारों की मुख्य आधार होती हैं। भारतीय महिलाओं को सदियों से 'गृह लक्ष्मी' कहा जाता है। घर की आय और खर्च का संतुलन बनाए रखने में उनकी विशेष भूमिका होती है। यदि महिलाएं अनावश्यक खर्चों को कम करें, जरूरत के अनुसार खरीदारी करें और बच्चों को भी बचत की आदत सिखाएं, तो परिवार आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। मैं समझती हूं कि आज डिजिटल युग में महिलाएं ऑनलाइन बैंकिंग, निवेश और बचत योजनाओं की जानकारी लेकर परिवार को आर्थिक सुरक्षा दे सकती हैं। यदि हर घर में समझदारी से खर्च हो, तो राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों की बचत संभव है। सच बात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार 'ऊर्जा बचाओ' और 'प्रकृति बचाओ' का संदेश दिया है। महिलाएं इस दिशा में बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं। मैंने महसूस किया है कि 'आत्मनिर्भर भारत' का सपना तभी पूरा होगा जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी। आज महिलाएं छोटे उद्योग, हस्तशिल्प, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, ऑनलाइन व्यवसाय और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं। किसी भी संकट-चाहे वह महामारी हो, आर्थिक मंदी हो या प्राकृतिक आपदा में महिलाओं का धैर्य और नेतृत्व परिवार को संभालने में मदद करता है। कोविड-19 महामारी के दौरान हमने देखा कि महिलाओं ने परिवार की देखभाल, स्वास्थ्य सुरक्षा और सीमित संसाधनों में घर चलाने का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। हमारे यहां महिलाएं परिवार के सदस्यों को सकारात्मक सोच, अनुशासन और संयम का पाठ पढ़ाकर मानसिक रूप से मजबूत बना सकती हैं। संकट के समय घबराने के बजाय समझदारी से निर्णय लेना ही सच्ची देशभक्ति है। सच यही है कि एक शिक्षित महिला पूरे परिवार को शिक्षित बनाती है। यदि महिलाएं बच्चों को ईमानदारी, अनुशासन, मेहनत और देशप्रेम के संस्कार दें, तो भारत का भविष्य मजबूत होगा। बचपन से ही बच्चों को संसाधनों की कीमत समझाना, देश के प्रति जिम्मेदारी सिखाना और समाज सेवा के लिए प्रेरित करना बहुत आवश्यक है। देखा जाए तो आज महिलाएं सोशल मीडिया और समाज में सकारात्मक संदेश फैलाकर लोगों को जागरूक कर सकती हैं। बच्चे का स्कूल से लेकर कालेज तथा बाद में कैरियर बनाने व शादी तक तथा परिवार चलाने में दादी-नानी बनकर महिलाओं की भूमिका उदाहरणीय है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को करुणा और सेवा का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं समाज में एकता, सहयोग और भाईचारे की भावना को बढ़ा सकती हैं। जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करना और सामाजिक कार्यों में भाग लेना राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने का सपना केवल सरकार के प्रयासों से पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए हर नागरिक, विशेषकर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। मैं व्यक्तिगत रूप से मानती हूं कि प्रधानमंत्री बचत और आत्मनिर्भरता की अपील केवल आर्थिक सुधार का संदेश नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान है। यदि भारत की महिलाएं इस संदेश को अपने जीवन में अपनाएं और परिवार को भी प्रेरित करें, तो हर संकट में भारत और अधिक मजबूत होकर उभरेगा। विश्लेषण किया जाए तो महिलाएं केवल परिवार की शक्ति नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रगति और सुरक्षा की आधारशिला बन सकती है। इस स्थिति में महिलाएं गृह लक्ष्मी के साथ-साथ राष्ट्र लक्ष्मी भी बन सकती हैं।

धार की भोजशाला की 'धार'

मेरा शुरू से ही यह मत रहा है कि काशी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा के श्रीकृष्ण जन्म स्थान में मुस्लिम समुदाय को अपना दावा वापस ले लेना चाहिए और इन धार्मिक स्थलों को सहर्ष हिन्दू समुदाय को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि भारत की मिली-जुली तहजीब की कैफियत यही है जिसमें दोनों समुदाय एक-दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं। काशी और मथुरा के धार्मिक स्थल चीख-चीख कर कह रहे हैं कि इनका मुस्लिम अर्काइव से कोई लेना-देना नहीं है और ये सिर्फ भारत में मुस्लिम आक्रमण के समय छोड़े गये निशान हैं। इनकी गहराई में आज जाने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इसी स्तम्भ में इस बारे में मैं पहले कई बार विस्तार से लिख चुका हूं। हम अब 21वीं सदी में जी रहे हैं और इस दौर के भारत को अपने पुराने जख्मों को समेटे रखने की कोई जरूरत नहीं है। हमें वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहिए और हिन्दू-मुसलमानों के बीच इतिहास द्वारा छोड़े गये कलुषता के चिन्हों को समाप्त करना चाहिए जिससे हमारी नई पीढ़ियां सुख-चैन से जी सकें और एक-दूसरे का आदर कर सकें। इस क्रम में मध्य प्रदेश के धार शहर में स्थित राजा भोज द्वारा निर्मित 'भोजशाला' का राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा मन्दिर घोषित किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है जिससे हमें पता चलता है कि भारत के कई इलाकों में ऐसे स्थल मौजूद हैं जो हिन्दू-मुसमानों के बीच पुराने जख्मों को कुरेदते हुए वैमनस्य पैदा करते हैं। बेशक आज के मुसलमानों का न तो 13वीं सदी के मुस्लिम सुल्तानों से कुछ लेना है और न ही 16वीं सदी के मुगल बादशाहों से। मुस्लिम राजाओं का लक्ष्य जाहिराना तौर पर भारत को समृद्ध बनाने का नहीं था बल्कि इस देश के वैभव से स्वयं को माला-माल करने का था। इस सिलसिले में मुगल बादशाह यादा अपवाद थे जिन्होंने कालान्तर में भारत को ही अपना घर बनाया और इसकी सुख-समृद्धि में हाथ बंटाया। मगर वे अपने साथ कुछ नहीं लाये थे उन्होंने जो कुछ भी यहां बनाया वह भारत की सम्पदा से ही बनाया, मगर इनमें से भी कई बादशाहों ने खास तौर पर औरंगजेब ने हिन्दू रियासत पर अपनी हुकूमत का रुआब गालिब करने की गर्ज से उनके धार्मिक स्थलों से छेड़छाड़ की और कुछ को इस्लामी तर्ज में ढालने के प्रयास भी किये। अतः बहुत स्पष्ट है कि स्वतन्त्र और धर्मनिरपेक्ष भारत के लोग इतिहास के बदनुमा दागों से छुटकारा पाने को लालायित हों। भोजशाला इसी का प्रमाण है। भारत के इतिहास के साथ एक त्रासदी यह भी है कि हमारी पीढ़ियों को गुप्त काल के बाद सीधे सुल्तानी आक्रमणी दौर में पहुंचा दिया जाता है और यह बताया ही नहीं जाता कि आठवीं सदी से लेकर 12वीं सदी के बीच का भारत कैसा था। राजा भोज 11वीं सदी के शुरू के दौर में 1010 से 1055 तक मध्य भारत में मालवा क्षेत्र में राज करने वाले ऐसे ही परमारवंशी महाप्रतापी राजा हुए जिनका शासन विदिशा से लेकर उत्तर में चित्तौड़ तक और दक्षिण पश्चिम में कौंकण क्षेत्र तक फैला हुआ था। उनकी राजधानी धार थी और यहीं उन्होंने विशाल शास्त्रीय नक्काशी वाला देवी सरस्वती या वाग्देवी का मन्दिर बनाया था जिसमें संस्कृत शोधशाला भी स्थापित की थी, मगर कालान्तर में इसी भोजशाला में एक मुस्लिम पीर मौला कमाल ने अपना डेरा जमा लिया जिससे इसका स्वरूप अर्ध इस्लामी हो गया और यहां मौला कमाल की मृत्यु के बाद नमाज अदा करने की भी रस्म शुरू कर दी गई। 1997 में भाजपा नेता साध्वी उमा भारती ने इसे हिन्दू मन्दिर व धार्मिक स्थल घोषित करने की मांग की व आन्दोलन भी चलाया। मामला अदालतों में पहुंच गया। जरा सोचिये राजा भोज का पीर मौला कमाल से क्या लेना-देना, मगर मुस्लिम सम्प्रदाय के लोग इसे मौला कमाल मस्जिद कहने लगे। यह इतिहास से छल नहीं तो और क्या है ! अतः मुस्लिम समुदाय को स्वयं सोचना चाहिए कि वे नाजायज मांग पर अड़े हुए थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इंदौर पीठ ने इस सिलसिले में हिन्दू पक्ष का यह दावा बिल्कुल सही माना कि भोजशाला मूलतः वाग्देवी मन्दिर ही है। विद्वान न्यायाधीशों सर्वश्री विजय कुमार शुक्ला व आलोक अवस्थी की पीठ ने निर्णय देते हुए कहा कि हमारे समक्ष जो ऐतिहासिक साहित्यिक साक्ष्य रखे गये हैं वे बताते हैं कि विवादित स्थल का मूल चरित्र भोजशाला का है जिसकी स्थापना राजा भोज ने एक संस्कृत ज्ञान पाठशाला के रूप में भी की थी। इन साक्ष्यों से पता चलता है कि यह भोजशाला वाग्देवी को समर्पित मन्दिर था। हमारे समक्ष रखे गये साक्ष्यों के अनुसार भोजशाला में शुरू से ही पूजा-अर्चना लगातार होती आ रही है जिसमें हिन्दू श्रद्धालु भाग लेते आ रहे हैं। हालांकि समय-समय के अनुसार इस परिपाटी का नियमन भी किया जाता रहा है मगर यह परंपरा समाप्त कभी नहीं हुई।

अतः यह संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि भोजशाला में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखा जाये और उनके ठहरने व आश्रय स्थलों के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता दी जाये। इसके साथ ही मन्दिर की शुद्धता और देवता की पवित्रता से समझौता न किया जाये। न्यायालय ने इस परिसर में कानून-व्यवस्था की स्थिति को भी चुस्त-दुरुस्त रखने के आदेश दिये हैं। विद्वान न्यायाधीशों ने अपने 240 के लगभग पृष्ठों के आदेश में लिखा है कि वे पुरातात्विक व ऐतिहासिक साक्ष्यों तथा स्थल की सर्वेक्षण रिपोर्ट और पुरातत्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि भोजशाला का कार्यभार पुरातत्व विभाग के पास ही है और वही इसकी देख-रेख भी करता है, मगर अप्रैल 2003 से भोजशाला में हर शुक्रवार को नमाज भी अदा की जा रही थी। वर्तमान आदेशों के बाद अब नमाज अदा नहीं होगी और मस्जिद के लिए सरकार धार में ही अन्यत्र जमीन

सम्पादकीय...

सके सतीशन

राहुल गांधी के करीबी सहयोगी के.सी. वेणुगोपाल को पहली बार बुधवार दोपहर को यह संकेत मिला कि वह अब केरल के मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे नहीं हैं। यह उस दिन हुआ जब पार्टी ने आधिकारिक तौर पर वी.डी. सतीशन के नाम की घोषणा की थी। उस शाम वेणुगोपाल के पक्ष में फैसला पक्का करने के लिए तय की गई एक बैठक अचानक रद्द कर दी गई और उनसे कहा गया कि वे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर न आएं। जाहिर है, प्रियंका गांधी, जो केरल के वायनाड से सांसद हैं, ने अपने हिचकिचाते भाई को सतीशन को चुनने के लिए मना लिया था। सतीशन पिछले पांच सालों से विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर राज्य में पार्टी का चेहरा रहे हैं। प्रियंका गांधी के सतीशन के साथ अच्छे संबंध हैं और आखिर वह केरल से सांसद भी हैं। अपनी मां सोनिया गांधी को भरोसे में लेते हुए, उन्होंने इस मामले में दखल देने का फैसला किया। गुरुवार सुबह, वेणुगोपाल को खड़गे के आवास पर बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि हाईकमान की पसंद सतीशन हैं। वेणुगोपाल के करीबी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस नेता का दिल टूट गया था। उन्होंने खड़गे और राहुल गांधी से गुहार लगाई और केरल में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी कड़ी मेहनत पर जोर दिया। यह बैठक दो घंटे तक चली, जिसमें दोनों नेताओं ने वेणुगोपाल को मनाने की कोशिश की। आखिरकार, वेणुगोपाल के पास कोई और चारा नहीं बचा था। उन्होंने आलाकमान से कहा कि वह पार्टी का फैसला मान लेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस के सिर्फ दो मुख्यमंत्री के. करुणाकरण और ओमन चांडी ही अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा कर पाए हैं। बाकी आठों ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, जिसकी मुख्य वजह पार्टी के भीतर मौजूद विरोधी गुटों का दबाव था। गुटबाजी से जूझ रहे केरल में सतीशन के सामने एक मुश्किल चुनौती है, खासकर तब जब बीजेपी, जो अपने बढ़े हुए वोट शेयर और विधानसभा में तीन सीटों से उत्साहित है, ने पहले ही यह प्रचार शुरू कर दिया है कि कांग्रेस ने अपने सहयोगी आईयूएमएल और जमात के दबाव के आगे घुटने टेक दिए हैं। तमिलनाडु में, जहां भाजपा के समर्थक नए मुख्यमंत्री विजय को ईसाई होने की वजह से ट्रोल कर रहे हैं, वहीं बड़ी ईसाई आबादी वाले राज्यों में नए मुख्यमंत्री के धर्म को लेकर जबरदस्त उत्सुकता और उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसा लगता है कि जिस दिन विजय जोसेफ ने सीएम के तौर पर शपथ ली, उस दिन उनके नाम में मौजूद 'जोसेफ' शब्द ने इंटरनेट पर सर्च ट्रैफिक को काफी बढ़ा दिया। उन्होंने शपथ लेते समय अपना पूरा नाम चंद्रशेखर जोसेफ विजय इस्तेमाल किया था। जो लोग इंटरनेट पर बारीकी से नजर रखते हैं, उन्होंने पाया कि गूगल सर्च में जबरदस्त उछाल आया। यह उछाल तब से सबसे ज्यादा था, जब इस अभिनेता ने चुनाव जीतकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी थी। इनमें से ज्यादातर सर्च केरल, गोवा, नगालैंड और मिजोरम जैसे राज्यों से आए थे, जहां ईसाइयों की अच्छी-खासी आबादी है।

मुसलमानों से घृणा करना अब फ़ैशन बना

मोदी ने खास संदर्भ के साथ यह बात कही लेकिन उनका कहना अनायास नहीं था। उन्होंने राज्य की भलाई के लिए रेवंत रेड्डी को अपने साथ आने की बात कही। इसका सीधा मतलब तो यह है कि रेवंत रेड्डी अगर प्रधानमंत्री का प्रस्ताव नहीं मानते हैं तो तेलंगाना की भलाई के लिए केंद्र सरकार की मदद नहीं मिलेगी। वैसे रेवंत रेड्डी को सत्ता संभाले अभी ढाई साल ही हुए हैं, इसलिए वे कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन उनके साथ दो बातें ऐसी हैं, जो संदेह पैदा करती हैं। पहली तो यह कि वे सोनिया और राहुल गांधी के प्रति बहुत ज्यादा स्वामीभक्ति दिखाते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर गांधी परिवार कहे तो वे एक हजार करोड़ रुपए भी जुटा कर दे सकते हैं। ऐसी स्वामीभक्ति की बातें करने वालों को लेकर हमेशा संदेह होता है। दूसरी बात यह है कि रेवंत रेड्डी काफी समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही कांग्रेस में आए थे।

सबको मालूम है कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कैसे हुआ। चुनाव आयोग ने एसआईआर के नाम पर करीब 91 लाख नाम काट दिए। इनमें 27 लाख 10 हजार तो ऐसे लोग हैं, जो जिंदा हैं, बंगाल में ही रहते हैं और उनके पास जरूरी दस्तावेज भी हैं, लेकिन तार्किक विसंगति के नाम पर उनके भी नाम हटाए गए, जिससे वे वोट नहीं डाल सके। इस तरह का पक्षपातपूर्ण एसआईआर जिस व्यक्ति की निगहबानी में हुआ, उस सुब्रत गुप्ता को चुनाव खत्म होते ही राज्य में नई बनी भाजपा सरकार का सलाहकार बना दिया गया। सुब्रत गुप्ता को पश्चिम बंगाल में एसआईआर की निगरानी के लिए विशेष पर्यवेक्षक बनाया गया था। यही नहीं, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में ही एसआईआर की प्रक्रिया, सुरक्षा बलों की तैनाती और पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। यह समझना मुश्किल नहीं है कि इन दोनों नियुक्तियों के जरिये भाजपा ने क्या मैसेज दिया है। भाजपा ने बताया है कि राजनीति में लोक लाज से उसका कोई संबंध नहीं है। दूसरा मैसेज राज्य की समूची नौकरशाही को है कि भाजपा किसी को भी कुछ भी दे सकती है। यह मैसेज साधारण नहीं है। ज्यादातर अधिकारी वैसे भी अच्छा पद पाने के लिए कुछ भी समझौता करने को तैयार रहते हैं। मुख्यमंत्री बनाए गए शुभेंदु अधिकारी को तो पूर्व में कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पूरे देश ने देखा ही था।

परजीवी होने में भाजपा और कांग्रेस का अंतर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को परजीवी पार्टी कहा है। उन्होंने यह बात पिछले सप्ताह दक्षिण भारत के दौरे पर उस समय कही जब तमिलनाडु में नई सरकार शपथ ले रही थी और मंच पर मुख्यमंत्री विजय के साथ राहुल गांधी भी मौजूद थे। मोदी का कांग्रेस को परजीवी कहना एक स्तर पर सही है। हालांकि अभी जिन तीन राज्यों-कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है वह सरकार उसने अपने दम पर बनाई है। चौथा राज्य केरल है, जहां कांग्रेस की सरकार बन रही है। वहां जरूर कांग्रेस एक क्षेत्रीय पार्टी के साथ मिल कर लड़ी। अगर दूसरी पार्टियों पर कांग्रेस की निर्भरता की बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्य हैं, जहां कांग्रेस निर्भर है। लेकिन ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस अकेले ही राजनीति करती है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जहां कांग्रेस गठबंधन में है लेकिन उसकी ताकत भी कम नहीं है और वहां गठबंधन नहीं होने से प्रादेशिक पार्टियों को नुकसान हो सकता है। बहरहाल, एक समय ऐसा भी रहा है जब कुछ राज्यों को छोड़ दें तो भाजपा भी हर जगह गठबंधन के सहारे ही चलती रही है। अटल बिहारी वाजपेयी ने छह साल तक अपनी सरकार करीब 25 पार्टियों के सहारे ही चलाई थी और इस समय मोदी सरकार भी कई पार्टियों के गठबंधन के सहारे ही चल रही है। अब अगर कांग्रेस और भाजपा के फर्क की बात करेंगे तो यह भी साफ दिखाई देगा। कांग्रेस जिन पार्टियों के साथ रही उनमें से ज्यादातर पार्टियां आज भी मजबूत स्थिति में हैं। दूसरी ओर भाजपा जिन पार्टियों के साथ रही वे आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं।

मुसलमानों से घृणा करना अब फ़ैशन बना

किसी भी चुनाव में भाजपा की जीत में हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा मुख्य कारक होता है, इसलिए उसका कोई भी नेता नफरती भाषण से परहेज नहीं करता है। लेकिन अब एक नया फैशन देखने को मिल रहा है। छोटे से लेकर बड़े नेता तक खुल कर कहने लगे हैं कि हमको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए' या हमको मुसलमान ने वोट नहीं दिया है' या हम मुसलमान का काम नहीं करेंगे।'। पहले इस तरह के बयान नहीं दिए जाते थे। चुनाव में उम्मीदवार हर जाति, समुदाय के लोगों से वोट मांगते थे और चुनाव के बाद सबका काम करने का संकल्प करते थे। हालांकि वह दिखावा ही होता था लेकिन अब ध्रुवीकरण की राजनीति ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है, जहां इस तरह के दिखावे को भी जरूरी नहीं माना जा रहा है। हैरानी की बात है कि इस किस्म के बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कोई कार्रवाई नहीं करता है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में यह बात प्रदेश के उस बड़े नेता ने कही, जो मुख्यमंत्री बना। उन्होंने बार-बार कहा कि हिंदू बूथों पर ही उनको वोट मिले हैं और नतीजों के बाद उन्होंने कहा कि वे मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। उनकी देखा-देखी अब बंगाल के ही दूसरे भाजपा विधायकों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि वे मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में तो पहले से ही कई विधायक ऐसा कहते रहे हैं। कुल मिला कर मुसलमानों के प्रति घृणा का खुला प्रदर्शन किया जाने लगा है।

अन्ना डीएमके का अस्तित्व खतरे में

अभी तत्काल तो नहीं कहा जा सकता है कि तमिलनाडु में अन्ना डीएमके का क्या होगा, क्योंकि इससे खराब स्थितियों के बाद भी तमिलनाडु की पार्टियों ने वापसी की है। 2011 के चुनाव में डीएमके ही 25 सीट के आसपास आ गई थी लेकिन उसने वापसी की। हालांकि अन्ना डीएमके का मामला थोड़ा अलग है। यह उन चुनिंदा प्रादेशिक पार्टियों में से है, जिसके संस्थापक नेता ने अपने परिवार से किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया है। एमजी रामचंद्रन इसके संस्थापक थे। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी जानकी रामचंद्रन ने पार्टी संभाली लेकिन वे कामयाब नहीं हुईं और जयललिता नेता बनीं। उन्होंने भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया और उनके निधन के बाद उनके दो करीबी नेताओं ओ. पनीरसेल्वम और ई. पलानीस्वामी में घमासान छिड़ गया। पनीरसेल्वम ने आखिरकार हथियार डाले और डीएमके के साथ चले गए। अब अन्ना डीएमके में फिर विभाजन हो गया है। सीवी षणमुगम 30 विधायकों को लेकर अलग हो गए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को समर्थन दे दिया है। पलानीस्वामी के साथ 17 विधायक बचे हैं। दूसरी ओर एक फोर्स के तौर पर विजय की पार्टी आ गई है और डीएमके में एमके स्टालिन के बाद उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन को पार्टी की कमान संभालना है। अन्ना डीएमके में जो हो रहा है उससे प्रमाणित होता है कि प्रादेशिक पार्टियों के संस्थापक नेताओं के परिवार का कोई व्यक्ति आगे नहीं आए तो पार्टी के सामने अस्तित्व का संकट होता है। अन्ना डीएमके पहले भी इसलिए बची क्योंकि उसे जयललिता जैसा करिश्माई नेतृत्व मिला था।

रेवंत रेड्डी को मोदी का प्रस्ताव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद की सभा में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को अपने साथ आने का प्रस्ताव दिया। मोदी ने खास संदर्भ के साथ यह बात कही लेकिन उनका कहना अनायास नहीं था। उन्होंने राज्य की भलाई के लिए रेवंत रेड्डी को अपने साथ आने की बात कही। इसका सीधा मतलब तो यह है कि रेवंत रेड्डी अगर प्रधानमंत्री का प्रस्ताव नहीं मानते हैं तो तेलंगाना की भलाई के लिए केंद्र सरकार की मदद नहीं मिलेगी। वैसे रेवंत रेड्डी को सत्ता संभाले अभी ढाई साल ही हुए हैं, इसलिए वे कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन उनके साथ दो बातें ऐसी हैं, जो संदेह पैदा करती हैं। पहली तो यह कि वे सोनिया और राहुल गांधी के प्रति बहुत ज्यादा स्वामीभक्ति दिखाते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर गांधी परिवार कहे तो वे एक हजार करोड़ रुपए भी जुटा कर दे सकते हैं। ऐसी स्वामीभक्ति की बातें करने वालों को लेकर हमेशा संदेह होता है। दूसरी बात यह है कि रेवंत रेड्डी काफी समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही कांग्रेस में आए थे। दूसरी ओर हिमंत बिस्वा सरमा और शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता हैं, जिनका संघ से कभी कोई जुड़ाव नहीं रहा, लेकिन जब भाजपा में गए तो वहां जाकर ऐसे रमे कि संघ के पुराने स्वयंसेवकों को भी मात देने लगे। सो, रेवंत रेड्डी के भीतर का स्वयंसेवक कब जाग जाए, वे भाजपा की ओर चल पड़ें, कहा नहीं जा सकता।

चुनावी रणनीतियां बनाएंगे नबीन

भाजपा के दोनों शिखर पुरुष अपनी पार्टी के युवा अध्यक्ष नितिन नबीन पर पूरा भरोसा दिखा रहे हैं। अपने नए अध्यक्ष को सियासी पैंतरों और अनूठा चुनावी रणनीतियों से लैस कर रहे हैं। आने वाले वर्ष यानी 2027 में कम से कम 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावी राज्यों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा और मणिपुर शामिल हैं। भाजपा शीर्ष की ओर से नबीन को यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे बूथ लेबल पर व्याप्त किसी भी प्रकार की विसंगतियों को दूर करने के प्रयास में अभी से जुट जाएं, जमीनी स्तर पर पार्टी के संगठन कौशल का आकलन कर अपनी निरपेक्ष रिपोर्ट तैयार करें। बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती व कमी का सम्यक आकलन करें। कमजोरियों की शिनाख्त करें और इसके निदान के उपाय सुझाएं। नबीन से कहा गया है कि वे खास कर पन्ना प्रमुखों की भूमिका पर ध्यान दें, उनसे संवाद स्थापित करें और पन्ना स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं की एक जागरूक टीम बनाने की पहल अभी से शुरू कर दें। बूथ प्रबंधन की कमियों को स्टडी के लिए अभी से जमीनी एजेंसियों से काम पर जुट जाने को कहें, जरूरी फीडबैक प्राप्त होने के बाद लोकल इन्फ्लुएंसर, लोकल कार्यकर्ता व प्रबुद्ध नेतागण के साथ मिल-बैठ कर नई रणनीतियों को परवान चढ़ाने के लिए 'ब्लूप्रिंट' तैयार करें, जिससे पार्टी का बूथ प्रबंधन पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो सके। इसके अलावा नबीन को एक महत्वपूर्ण कार्य और भी सौंपा गया है कि वे पार्टी के संभावित उम्मीदवारों की सीटवार सूची तैयार करवाएं। इस चयन के लिए कई मानक पहले से तय हैं, नबीन की टीम इन मानकों को और भी धार देने पर काम कर रही है, संभावित उम्मीदवारों के चयन के कुछ प्रमुख पैमाना मसलन उम्मीदवार अपने एरिया में कितना पॉपुलर है? उसकी जीत की संभावना कितनी है? वह स्थानीय कारकों में कितना 'फिट' बैठता है आदि-आदि। जाहिर है यह कदम भाजपा की उस केंद्रीय नीति का अहम हिस्सा है जिसमें वह 2027 के चुनावों के पहले अपने विभिन्न संगठनों को और मजबूत करना चाहती है।

अपनी नवीन टीम को अंतिम रूप देते नितिन

भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नबीन को पार्टी की अध्यक्षीय जिम्मेदारी संभाले छह महीनों से भी ज्यादा का वक्त हो गया, पर अब तक वे अपनी पुरानी टीम यानी नड्डा की टीम से ही काम चला रहे हैं। पर कहते हैं अब अध्यक्ष ने अपनी नई टीम का एक नया खाका तैयार कर लिया है, आने वाले कुछ दिनों में इसकी घोषणा हो सकती है। यह भी कयास लग रहे हैं कि नबीन की नई टीम में ज्यादातर पुराने चेहरे ही कायम रहेंगे। पहले यह सुना जा रहा था कि बीएल संतोष की जगह बंगाल चुनाव में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके सुनील बंसल को नया संगठन महामंत्री बनाया जाएगा, पर कहते हैं संघ अभी संतोष को और भी मौके देने के पक्ष में है, चुनांचे उन्हें नहीं छेड़ा जाएगा। विनोद तावड़े को भी बतौर महासचिव उनकी गद्दी सलामत रह सकती है।

राम माधव के रूप में टीम नबीन को एक नया महामंत्री मिल सकता है। सबसे ज्यादा पेंच एक ब्राह्मण चेहरे को पार्टी संगठन में महती भूमिका देने को लेकर फंसा है। पार्टी का एक गुट इस कोटे से बिहार के पूर्व मंत्री मंगल पांडेय का नाम आगे बढ़ा रहा है, तो सुधांशु त्रिवेदी भाजपा के एक बड़े नेता की निजी पसंद के तौर पर फिलवक्त रेस में आगे दिखते हैं। वैसे भी मंगल पांडेय से एक बार नितिन नबीन की तकरार पहले भी हो चुकी है। जब इस बार बिहार में सम्राट मंत्रिमंडल के मंत्रियों के चयन पर मंथन बैठक चल रही थी तो मंगल पांडेय अपनी ओर से दिनारा, रोहतास के विधायक आलोक कुमार सिंह का नाम आगे बढ़ा रहे थे, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के टिकट पर चुनाव जीते हैं। मंगल पांडेय की बात को मीटिंग में विनोद तावड़े का वीटो हासिल था, तावड़े का कहना था 'आलोक सिंह शाहबाद क्षेत्र से एक सशक्त राजपूत चेहरे का प्रतिनिधित्व करते हैं', तो वहीं नबीन का कहना था कि -हमारे पास इस क्षेत्र से पहले से ही संजय टाइगर हैं। इस पर तावड़े ने कहा कि 'टाइगर का परफॉरमेंस बतौर मंत्री कुछ खास नहीं रहा है', इस पर नबीन का कहना था कि 'आप महज तीन महीनों में किसी नेता की परफॉरमेंस कैसे आंक सकते हैं?' स्मरण रहे कि संजय टाइगर विद्यार्थी परिषद के जमाने से नितिन नबीन के साथ काम कर चुके हैं।

अटकी क्यों हैं पटना हाई कोर्ट में जजों की नियुक्तियां

26 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से हरी झंडी मिलने के बावजूद पटना हाई कोर्ट में 9 जजों की नियुक्ति का मामला अभी भी अधर में लटका हुआ है। ये सभी अधिवक्ता हैं, जिन्हें जज के रूप में नियुक्त करने की अनुमति मिल गई है। माना जा रहा है कि अभी भी यह फाइल लॉ-मिनिस्ट्री में अटकी हुई है। विश्वस्त सूत्र इस लिस्ट की अभी तक तामील न हो पाने की दो वजहें बता रहे हैं, एक तो इन नौ प्रस्तावित जजों की लिस्ट में एक नाम पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता का है। सूत्र बताते हैं कि इससे पहले भी दो बार उनका नाम अनुमोदन के लिए दिल्ली भेजा गया था, पर कुछ कारणों से इनके नाम को हरी झंडी नहीं मिल पाई थी जबकि इनकी गिनती पटना के बेहद काबिल वकीलों में होती है। वहीं बिहार वालों को ऐसा भी लग रहा है कि जानबूझ कर बिहार की लिस्ट को लंबित रखा जा रहा ताकि अन्य राज्यों के हाई कोर्ट में तब तक पहले से वहां जजों की नियुक्ति हो सके, जाहिर है इससे सुप्रीम कोर्ट तक के सफर में बिहार हाई कोर्ट के जज वरिष्ठता के आधार पर पिछड़ सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार से जुड़े कुछ विश्वस्त सूत्र खुलासा करते हैं कि इन नौ लोगों की लिस्ट में कुछ नामों पर सरकार को आपत्ति है, सो इनमें से कुछ चुनिंदा लोगों के नाम ही नोटिफिकेशन में जारी हो पाएंगे।

क्या डीएमके भी भाजपा का हाथ थामेगी?

वहीं दूसरी ओर टीवीके से हार का भारी दंश झेलने के बाद डीएमके में भी सब कुछ सामान्य नहीं है। जब से कांग्रेस ने विजय को समर्थन का ऐलान किया है डीएमके ने कांग्रेस से कुट्टी कर ली है अब वह सदन में भी कांग्रेस की बगलगीर नहीं रहना चाहती, इस बारे में पार्टी ने पहले ही लोकसभा स्पीकर से कह दिया है कि 'उनके सांसदों के लिए कांग्रेस से अलग बैठने की व्यवस्था की जाए।' स्मरण रहे कि डीएमके के लोकसभा में 22 और राज्यसभा में 8 सांसद हैं। इस दफे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उनके 59 तथा पुडुचेरी में 5 विधायक विजयी रहे हैं। डीएमके नेताओं का एक वर्ग ऐसा भी है जो चाहता है कि पार्टी भाजपा के समर्थन में खुलेआम उतर जाए, इस बात की पैरवी डीएमके नेता राजा और कनिमोझि कर रहे हैं। शायद इसी बात से नाराज होकर स्टालिन पुत्र उदयनिधि ने सनातन के खिलाफ इतना कड़ा बयान दे दिया। वहीं पार्टी प्रमुख स्टालिन भी भाजपा के साथ जाने के पक्ष में नहीं बताए जाते, उनका स्पष्ट तौर पर मानना है कि 'डीएमके भले ही एक क्षेत्रीय पार्टी है पर वह द्रविड़ियन पहचान की झंडाबरदार है, जो सामाजिक न्याय व राज्यों की स्वायत्ता की प्रबल पैरोकारों में से है, सो ऐसी पार्टियों को कम से कम भाजपा के साथ एक मंच पर नहीं दिखना चाहिए।' राहुल नबीन की जगह ईडी को एक मुखिया मिलने की चर्चा जोरों पर है, यह नाम है आईआरएस अफसर मनीष कुमार का, जो फिलवक्त दिल्ली कस्टम के चीफ कमिश्नर हैं। इससे पहले ये डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल कस्टम में कार्यरत थे। यह एक बेहद लो-प्रोफाइल अफसर हैं, जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के सगे छोटे भाई भी हैं। इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस जुटाने में इन्हें महारथ हासिल बताया जाता है। इन्होंने अपनी पढ़ाई-लिखाई दिल्ली के हिंदू कॉलेज से की है, इसके बाद इन्होंने इंटरनेशनल लॉ और टैक्सेशन्स में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री भी हासिल की है। दो दशकों से ज्यादा का वक्त यह अपनी सरकारी सेवा को दे चुके हैं। राहुल नबीन अगस्त 2026 में अपने पद से रिटायर हो रहे हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैण्डवाला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। ([illegible])

एसएचजी मेला-2026- महिला स्टार्टअप्स को 10 करोड़ तक बिना गारंटी लोन देगी दिल्ली सरकार, सीएम रेखा गुप्ता ने की घोषणा

नई दिल्ली ।

दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपये तक का बिना गिरवी ऋण दिया जाएगा, जिसकी गारंटी खुद दिल्ली सरकार लेगी। सरकार अब मॉल और बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में महिलाओं के स्वदेशी उत्पादों को नियमित बाजार भी उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री शनिवार को रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास यूनिटी वन मॉल में आयोजित दो दिवसीय मेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप (एसएचजी) मेला-2026 के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी की महिलाओं को आत्मनिर्भर और उद्यमी बनाने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है।

10 करोड़ का कोलैटरल-फ्री लोन देगी सरकार

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि महिला स्वयं सहायता समूहों और महिला स्टार्टअप्स के लिए 10 करोड़ रुपये तक का कोलैटरल-फ्री लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऋण के लिए महिलाओं को कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी होगी और इसकी गारंटी दिल्ली सरकार खुद लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि यादा से यादा महिलाएं छोटे उद्योग, हस्तशिल्प और घरेलू कारोबार से जुड़ें और अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाएं।

बेहद खास हैं स्वदेशी उत्पाद

सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाओ,

आत्मनिर्भर भारत और वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट विजन को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे मेले अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में बने हस्तशिल्प, खादी और घरेलू उत्पाद गुणवत्ता में किसी से कम नहीं हैं, जरूरत सिर्फ बेहतर मार्केटिंग और प्लेटफॉर्म की है।

स्वदेशी उत्पादों के लिए तय होगी जगह

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार अब मॉल और बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्वदेशी उत्पादों के लिए नियमित जगह उपलब्ध कराएगी, ताकि महिलाओं द्वारा तैयार सामान को बड़ा बाजार मिल सके। उन्होंने लोगों से विदेशी वस्तुओं की बजाय स्थानीय और स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील भी की।

मेले में कई बैंकों को किया शामिल

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं की बैंकिंग और वित्तीय पहुंच मजबूत करने पर भी काम कर रही है। इसी वजह से मेले में विभिन्न बैंकों को भी शामिल किया गया, ताकि महिलाओं को आसान ऋण और वित्तीय सलाह मिल सके। मेले में करीब 24 स्वयं सहायता समूहों ने हिस्सा लिया। यहां हस्तशिल्प, क्रोशिया कार्य, खादी, घरेलू उत्पाद, खाद्य सामग्री और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी और बिक्री की गई। उत्तर पश्चिम जिले के वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट के तहत हस्तशिल्प उत्पादों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में सांसद योगेंद्र चंदोलिया, विधायक कुलवंत राणा, उत्तर पश्चिम जिले की डीएम सौम्या सौरभ, बैंक प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्य मौजूद रहीं। मेले का आयोजन उत्तर पश्चिम जिला प्रशासन ने किया है।

छोटी कोशिशें कर रहीं महिलाओं को मजबूत

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की छोटी-छोटी कोशिशें न सिर्फ परिवार की आय बढ़ा रही हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रही हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि ऐसे आयोजनों से महिलाओं को नया बाजार, पहचान और रोजगार के अवसर मिलेंगे।

हरियाणा पुलिस का दावा- महिला अपराधों में आई गिरावट, जारी किए आंकड़े

चंडीगढ़ । हरियाणा पुलिस ने महिला सुरक्षा को लेकर लागू की गई व्यापक रणनीति ने उल्लेखनीय परिणाम का दावा किया है। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 38 प्रतिशत की बड़ी कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2024 में जहां ऐसे मामलों की संख्या 13,945 थी। वहीं, 2025 में यह घटकर 8,723 रह गई। यह बदलाव केवल आंकड़ों का सुधार नहीं, बल्कि सुरक्षा तंत्र में बड़े स्तर पर हुए सुधार का संकेत है। राय में दुष्कर्म, अपहरण और घरेलू हिंसा जैसे गंभीर अपराधों में लगातार गिरावट आई है। पुलिस ने महिला सुरक्षा को घर, कार्यस्थल, यात्रा और न्यायिक प्रक्रिया इन चार स्तरों पर मजबूत किया है। प्रदेशभर में 33 महिला थाने और 365 महिला हेल्प डेस्क घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और

अन्य मामलों में पीड़ित महिलाओं को त्वरित सहायता दे रहे हैं। कामकाजी महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए डायल-112 के तहत 94 हजार से अधिक महिलाओं को ट्रिप मॉनिटरिंग सेवा से जोड़ा गया है, जिससे उनकी यात्रा की रियल-टाइम निगरानी की जा रही है। दुर्गा शक्ति मोबाइल ऐप और रैपिड एक्शन फोर्स की सक्रिय गश्त ने सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा को और मजबूत किया है। महिला उत्पीड़न के मामलों में आरोपियों पर सरकारी लाभ रोकने जैसी सख्त कार्रवाई ने भी स्पष्ट संदेश दिया है। पुलिस मुख्यालय स्तर पर विशेष निगरानी व्यवस्था और तेज सुनवाई की प्रणाली ने महिलाओं से जुड़े मामलों के 98 प्रतिशत निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हरियाणा अब महिला सुरक्षा के क्षेत्र में एक प्रभावी मॉडल के रूप में उभर रहा है।

हरियाणा में जनगणना के कार्य में तेजी

चंडीगढ़ ।

हरियाणा में चल रही जनगणना 2027 के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं आवास गणना (एचएलओ) के कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है राय के अधिकांश क्षेत्रों में हाउस लिस्टिंग गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, नगर निगम आयुक्तों, जिला शिक्षा अधिकारियों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा बैठक कर इस राष्ट्रीय कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा करने की तैयारियों का आकलन किया। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनगणना कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और इसे पूरी प्रतिबद्धता, जवाबदेही और दक्षता के साथ संपन्न करें। उन्होंने कहा कि जनगणना नीति निर्माण, विकास योजनाओं की रूपरेखा, संसाधनों के आवंटन और कल्याणकारी योजनाओं

कई जिलों में हाउस लिस्टिंग गतिविधियां सौ फीसदी शुरू

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने की समीक्षा बैठक

फील्ड कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश

के क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। इसलिए इसका सफल संचालन शासन और प्रशासन के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि कोई कर्मचारी जनगणना ड्यूटी में लापरवाही या असहयोग करता है तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के जनगणना संचालन निदेशक डॉ. ललित जैन ने जानकारी दी कि राय में कुल हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स (एचएलबी) में से 97 प्रतिशत से अधिक में कार्य प्रारंभ हो चुका है। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, फतेहाबाद, हांसी, चरखी दादरी और फरीदाबाद जिलों में हाउस लिस्टिंग गतिविधियां शत- प्रतिशत प्रतिशत शुरू हो चुकी हैं, जो जिला प्रशासन, गणनाकारों और पर्यवेक्षी स्टाफ की दक्षता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चरखी दादरी जिला 32 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण कर राय में अग्रणी है, जबकि फतेहाबाद, हांसी, जींद और महेंद्रगढ़ जिलों में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। शहरी क्षेत्रों में भी कार्य की गति संतोषजनक है। नगर निगमों में पानीपत में सर्वाधिक कार्य पूरा हुआ है, इसके बाद रोहतक और फरीदाबाद का स्थान है। बैठक के दौरान राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने जनगणना कार्य के सुचारू संचालन के लिए नगर समितियों, सरपंचों, पंचों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (आरडब्ल्यूए) के सक्रिय सहयोग पर बल दिया। उन्होंने ग्राम सभाओं को भी जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करने और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियां चलाने का आह्वान किया। सभी जिला प्रशासन को सलाह दी गई कि जनगणना ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के कार्य समय को आवश्यकतानुसार समायोजित किया जाए, ताकि फील्ड कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जा सके। मुख्य सचिव ने 15 जून, 2026 से शुरू होने वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) की तैयारियों की भी समीक्षा की। अधिकारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित करने तथा जनगणना और एसआईआर कार्यों के बीच तालमेल बनाए रखने पर चर्चा की, ताकि बीएलओ और फील्ड स्टाफ पर कार्य का अनावश्यक दबाव न पड़े। मुख्य सचिव ने कहा कि जनगणना कार्य में लगे बीएलओ को 31 मई, 2026 तक निर्वाचन संबंधी कार्यों से छूट दी जा सकती है। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्री डी. के. बेहरा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

इस्तीफा मांगना आसान, काम करके दिखाना मुश्किल, धर्मेंद्र प्रधान सबसे सक्षम मंत्रियों में से एक - ऊर्जा मंत्री अनिल विज

चंडीगढ़ । हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आजकल राजनीति में बिना सोचे-समझे इस्तीफा मांगना एक कॉमन बात बन गई है। किसी से भी खड़े होकर इस्तीफा मांग लेना बहुत आसान है, लेकिन असली बात काम करके दिखाने की होती है। मंत्री आज मीडियाकर्मियों से बातचीत कर रहे थे। श्री विज ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान का बचाव करते हुए कहा कि वे केंद्र सरकार के सबसे सक्षम और मेहनती मंत्रियों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही यह घटना सामने आई, केंद्र सरकार ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं और दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार

इस मामले को लेकर पूरी तरह गंभीर है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाने के संबंध में श्री अनिल विज ने कहा कि भगवंत मान को शायद प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का उद्देश्य समझ नहीं आता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशहित में विदेश यात्राएं करते हैं ताकि भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंध मजबूत हों, व्यापार बढ़े और दुनिया में भारत की स्थिति और सशक्त बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हित में कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व से भारत की वैश्विक छवि को नई ऊंचाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कोरोना महामारी जैसी बड़ी चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया। इसके अलावा अनेक कठिन परिस्थितियों के तहत आपरेशन सिंदूर में भी प्रधानमंत्री ने अपनी दूरदर्शी सोच और मजबूत नेतृत्व से देश को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। श्री विज ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और युद्ध जैसे हालातों के बीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को हर चुनौती से सुरक्षित बाहर निकालने में पूरी तरह सक्षम हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत न केवल सुरक्षित रहेगा बल्कि विश्व में और अधिक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरेगा।

बागवानी अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा सिरसा में स्थापित होने वाला किन्नू प्लांट - डॉ. अरविंद शर्मा

चंडीगढ़ । (संवाददाता) हरियाणा के सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री और डेयरी फेडरेशन मिलकर सिरसा स्थित वीटा प्लांट परिसर में अत्याधुनिक किन्नू जूस प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं। इससे सिरसा व आसपास के क्षेत्रों के किन्नू उत्पादकों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा तथा उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त जूस उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि पीपीपी मोड पर स्थापित होने वाले इस प्लांट के लिए निजी क्षेत्र के निवेशकों से प्रस्ताव मांगे गए हैं।

रविवार को सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने अपने संक्षिप्त प्रवास के दौरान वीटा प्लांट सिरसा का औचक निरीक्षण करते हुए वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सीईओ वीटा दिनेश मेहता एवं अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि वीटा प्लांट की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, ताकि किसानों और दुग्ध उत्पादकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की घोषणा के अनुरूप सिरसा में जल्द ही अत्याधुनिक किन्नू जूस प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के किन्नू उत्पादक किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि सिरसा जिला बागवानी, विशेषकर किन्नू उत्पादन के क्षेत्र में पूरे प्रदेश में विशेष पहचान रखता है। यहां के किसान बड़े स्तर पर किन्नू की खेती करते हैं, लेकिन फसल के उचित प्रसंस्करण और विपणन की कमी के कारण उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। इसी को ध्यान में रखते हुए किन्नू प्लांट स्थापित करने की योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि वीटा प्लांट परिसर में तीन एकड़ भूमि को इसके लिए चिन्हित किया जा चुका है। इस परियोजना को पीपीपी मोड पर स्थापित करने के संबंध में कैबिनेट कमेटी ऑफ सेक्रेट्रीज (कोसी) की बैठक में भी चर्चा हो चुकी है। इसके बाद निजी क्षेत्र के निवेशकों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किन्नू प्लांट शुरू होने के बाद किन्नू के साथ-साथ अन्य फलों से भी जूस तैयार किया जाएगा। इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। साथ ही, इलाके में फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बेगू रोड स्थित भगवान परशुराम ब्राह्मण धर्मशाला में राष्ट्रीय ब्राह्मण सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।

प्रधानमंत्री मोदी की अपील से प्रेरित होकर विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने गुरुग्राम से चंडीगढ़ तक किया ट्रेन का सफर

(संवाददाता)

चंडीगढ़ । हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रहित में ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के उचित उपयोग को लेकर किया गया आह्वान आज पूरे देश के लिए प्रेरणा का विषय है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार भी लगातार जनहित में कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से प्रेरित होकर श्री कृष्ण लाल पंवार गुरुग्राम से चंडीगढ़ तक ट्रेन से यात्रा कर सोमवार को होने वाली हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निजी वाहन और सरकारी काफिले का उपयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज समय की मांग है कि प्रत्येक नागरिक अपनी

निजी वाहनों का कम उपयोग राष्ट्रहित और पर्यावरण दोनों के लिए जरूरी- कृष्ण लाल पंवार

जिम्मेदारी समझे और जहां संभव हो वहां निजी वाहनों का कम से कम उपयोग करे। उन्होंने कहा कि यदि सक्षम लोग भी छोटी-छोटी यात्राओं में निजी वाहनों के बजाय ट्रेन, बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों का उपयोग करें, तो इससे ईंधन की बचत के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं, ट्रैफिक जाम और प्रदूषण में भी कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं अपने फ्लीट में न्यूनतम वाहनों के उपयोग का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनके कारकेड में सुरक्षा की दृष्टि से केवल आवश्यक वाहन ही शामिल होंगे। इसके साथ ही उन्होंने सप्ताह में एक दिन बिना किसी वाहन के कार्य करने का भी संकल्प लिया है, ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए और लोग ईंधन बचत के प्रति जागरूक हों। पंचायत मंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर ईंधन बचत के इस अभियान में सहभागी बनें। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिवर्तन का आधार बनते हैं और सामूहिक भागीदारी से ही स्वच्छ, सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल भविष्य का निर्माण संभव है।

पानी संकट से निजात की उम्मीद बने 101 जलाशयों का कायाकल्प महाअभियान शुरू, संधू ने आरंभ किया संचय अभियान

दिल्ली । भीषण गर्मी और गहराते जल संकट से निजात पाने के लिए राजधानी में बड़ी पहल शुरू हुई है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने पश्चिम विहार के डिस्ट्रिक्ट पार्क से डीडीए के जल संचय अभियान का शुभारंभ किया। इसके तहत पहले चरण में दिल्ली के 101 प्रमुख जलाशयों का कायाकल्प किया जाएगा, जिसका सीधा उद्देश्य राजधानी के सूखते भूजल को फिर से जीवित करना है। यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली ऐतिहासिक रूप से अपनी बावलियों, जलाशयों और प्राकृतिक धाराओं के लिए जानी जाती थी, जो अतिक्रमण और अतिक्रमण की भेंट चढ़ गए। उपराज्यपाल ने कहा कि यह केवल जलाशयों के सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन और स्थायी जल प्रबंधन की दिशा में एक ठोस कदम है। उपराज्यपाल ने निर्देश दिए कि पहले चरण के तहत चिह्नित सभी 101 जलाशयों के जीर्णोद्धार का काम 30 अगस्त तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। इसके पीछे मुख्य रणनीति यह है कि मानसून की बारिश शुरू होने से पहले इन जलाशयों की ड्रेजिंग (मिट्टी निकालना), खुदाई और सफाई का काम पूरा हो जाए। इन जलाशयों के प्राकृतिक जलग्रहण (कैचमेंट) क्षेत्रों को भी साफ किया जा रहा है, ताकि बारिश का एक-एक बूंद पानी बिना किसी रुकावट के इन तालाबों तक पहुंचे और जमीन के भीतर जाकर भूजल स्तर को बढ़ा सके। इनमें से 101 पर युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है। जल संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाले इलाकों को इस योजना में प्राथमिकता दी गई है। करीब 155 हेक्टेयर (383 एकड़) क्षेत्र में फैले इन 101 जलाशयों में सबसे अधिक 22 जलाशय द्वारका जोन में हैं। इसके अलावा दक्षिण दिल्ली में 13, रोहिणी में 17 और नरेला में 6 जलाशयों का कायाकल्प किया जाएगा। पश्चिम विहार के जिस डिस्ट्रिक्ट पार्क से अभियान शुरू हुआ, वहां का 1.47 हेक्टेयर का जलाशय भी इस सूची में शामिल है। अभियान के दूसरे चरण की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है, जिसे मई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है, ताकि जलाशयों में केवल साफ पानी ही रहे। इनके चारों ओर बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा, ताकि ये इलाके दिल्ली के 'फेफड़े' के रूप में भी काम कर सकें। इस अवसर पर विधायक कर्नैल सिंह और डीडीए उपाध्यक्ष एन. सरवण कुमार भी मौजूद रहे। महाअभियान के तहत दिल्ली के अलग-अलग जोनों में स्थित जिन 101 जलाशयों को पुनर्जीवित किया जा रहा है इनमें द्वारका क्षेत्र के बामनोली, ढ्यासपुर, छावला कलां, खरखरी रोड, हिरन कलां, छावला (दो जलाशय), बिजवासन कलां (तीन जलाशय), कुतुबुल्ली (दो जलाशय), कांगनपुर, रेवला खानपुर, नजफगढ़ (दो जलाशय), कमरुद्दीन नगर, मुंडका, बक्करवाला (दो जलाशय), हस्तसाल और दौलतपुर शामिल हैं। दक्षिण दिल्ली में जसोला, मैदानगढ़ी, किशनगढ़, निजामुद्दीन, सैदुलाजाब (दो जलाशय), लाडो सराय, महिपालपुर, रंगपुरी (तीन जलाशय), महरौली और किशनगढ़ की सूखी बहने वाली क्रीक क्षेत्र में मैदानगढ़ी (दो जलाशय), सुल्तानपुर डबास, कंझावला (दो जलाशय), मदनपुर डबास, पूठ कलां (दो जलाशय), घेवरा, कुतुबगढ़ माजरा (दो जलाशय), रानी खेड़ा, नांगल ठाकरान (दो जलाशय), मुबारकपुर और निजामपुर को चुना गया है। नरेला जोन में बवाना (दो जलाशय), मामूरपुर, सिंघू खुर्द (दो जलाशय) और लामपुर इस सूची का हिस्सा हैं। अन्य इलाकों के अकबरपुर माजरा, अलीपुर, बख्तावरपुर (तीन जलाशय), बुराड़ी, बेगमपुर, झिमरी (दो जलाशय), इब्राहिमपुर, खेड़ा कलां, नांगली पूना, रामपुर, मियानपुर, तिगीपुर, सलेमपुर, बुराड़ी और कमालपुर माजरा बुराड़ी (चार जलाशय), शालीमार मोहम्मदपुर, पश्चिम विहार का डिस्ट्रिक्ट पार्क, मटियाला (दो जलाशय), किलोकरी, कालिंदी अविहार (तीन जलाशय), मौज गुजरान खादर, उस्मानपुर, नेल्सन मंडेला की सूखी झील (संजय लेक), झड़ौदा माजरा, ठोकपुर (तीन जलाशय), हिरण झील, सरिता विहार फेज, रोहिणी सेक्टर-20 और 23 के जलाशय, किला, बदरपुर का सुरजा लेक, सूरज कुंड का मेला, तालकटोरा का आसफ कुंड और फलावा जैसे महत्वपूर्ण जल स्रोतों को नया जीवन दिया जाएगा।

ट्रंप ने फिर दी धमकी- कहा- यूरेनियम पर जल्द फैसला ले ईरान, वरना दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा नाम

वर्ल्ड डेस्क । (वेबवार्ता) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर चेतावनी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान के लिए अब समय हाथ से निकला जा रहा है। उसे बहुत तेजी से कदम उठाने होंगे। अगर उसने जल्द फैसला नहीं लिया, तो उसका नामोनिशान मिट जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कहा कि इस समय वक्त की भारी कमी है। दोनों देशों के बीच महीनों से चल रहे भयंकर संघर्ष के बाद अब कूटनीतिक गतिरोध और ज्यादा गहरा गया है।

अमेरिका ने रखीं बेहद सख्त शर्तें

ईरानी मीडिया फारस न्यूज एजेंसी ने हाल ही में अमेरिका की कुछ गुप्त शर्तों का खुलासा किया था। इसके कुछ ही घंटे बाद ट्रंप का यह गुस्सा फूट पड़ा। अमेरिका ने बातचीत शुरू करने के लिए ईरान के सामने तीन बेहद कड़े नियम रखे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपना 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम तुरंत उसे सौंप दे। इसके साथ ही उसे अपने केवल एक परमाणु संयंत्र को चालू रखने की इजाजत मिलेगी। अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि युद्ध में हुए नुकसान का कोई मुआवजा ईरान को नहीं दिया जाएगा।

ईरान ने ठुकराया अमेरिकी प्रस्ताव

दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिकी प्रशासन की इन सभी शर्तों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान ने बातचीत की मेज पर आने के लिए अपनी खुद की पांच शर्तें सामने रख दी हैं। ईरान की मांग है कि उस पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध तुरंत हटाए जाएं। इसके साथ ही उसने युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपने पूर्ण नियंत्रण को मान्यता देने की शर्त रखी है।

पाकिस्तानी मध्यस्थता भी रही बेअसर

पश्चिम एशिया में ईरान, इस्राइल और अमेरिकी सेना के बीच हफ्तों तक भीषण जंग चली थी।

इसके बाद इसी साल पाकिस्तान की मध्यस्थता से एक नाजुक युद्धविराम हुआ था। इस शांति समझौते के बाद भी दोनों देशों के बीच का तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। संवर्धित यूरेनियम के भंडार, आर्थिक पाबंदियों और मुआवजे के विवाद ने शांति की हर कोशिश को पूरी तरह नाकाम कर दिया है। यह गंभीर विवाद लगातार

आपदाओं का विभाग बन गया है शिक्षा मंत्रालय, राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान पर बोला हमला

नई दिल्ली । (वेबवार्ता) लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हुए कहा कि बार-बार परीक्षा पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री को अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया. राहुल गांधी लगातार नीट पेपर लीक मामले को उठा रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए. राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा कि साल 2024 में नीट पेपर लीक हुआ था, लेकिन परीक्षा रद्द नहीं हुई और न ही किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया. उस समय मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई और एक कमेटी बनाई गई. उन्होंने कहा कि अब 2026 में फिर नीट पेपर लीक हुआ. इस बार परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन शिक्षा मंत्री ने फिर भी इस्तीफा नहीं दिया. मामले की जांच फिर सीबीआई कर रही है और अब एक नई कमेटी बनाई जाएगी. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से सीधे तीन सवाल पूछे. उन्होंने कहा कि देश जवाब चाहता है कि बार-बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं. उन्होंने पूछा कि परीक्षा पे चर्चा पर सरकार चुप क्यों है और लगातार विफल हो रहे शिक्षा मंत्री को पद से क्यों नहीं हटाया जा रहा. एक अन्य पोस्ट में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार जिम्मेदारी लेने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश करती है. उन्होंने लिखा कि पहले सरकार लंबे समय तक चुप रहती है, फिर दोषियों को संरक्षण देती है और सवाल उठाने वालों पर हमला किया जाता है. राहुल गांधी ने कहा कि नीट पेपर लीक के बाद भी किसी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 2024 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डीजी को हटाकर बाद में मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बना दिया गया. राहुल गांधी ने एक अन्य पोस्ट में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने 22 लाख नीट छात्रों के साथ धोखा किया है और संसद का भी अपमान किया है. राहुल गांधी का आरोप है कि संसदीय समिति की रिपोर्ट को सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि उसमें विपक्षी सांसद शामिल थे. उन्होंने कहा कि जो सरकार संसद पर भरोसा नहीं करती, वह नीट सुधारों पर क्या भरोसा देगी. राहुल गांधी ने मांग की कि शिक्षा मंत्री को तुरंत हटाया जाए. नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का गुस्सा भी लगातार बढ़ता जा रहा है. शनिवार को एनएसयूआई के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने एनटीए दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि एनटीए और मोदी सरकार ने नीट घोटाले के जरिए छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया है. प्रदर्शनकारियों ने दो प्रमुख मांगें रखीं. पहली, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए और दूसरी,

स्वीडन में गूंजा भारत का डंका

पीएम मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान, रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से नवाजा

इंटरनेशनल डेस्क । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक साख में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया है। स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी को वहां के प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें भारत और स्वीडन के बीच संबंधों को मजबूती देने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है।

प्रधानमंत्री का 31वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान

यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के नाम दर्ज अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों में 31वां सम्मान है। उल्लेखनीय है कि रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार किसी भी सरकार के प्रमुख को दिया जाने वाला स्वीडन का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। इस पुरस्कार की ऐतिहासिकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी स्थापना वर्ष 1748 में की गई थी। स्वीडन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यह सम्मान स्वीडिश हितों के लिए किए गए विशेष कार्यों, सार्वजनिक गतिविधियों में योगदान और सरकारी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने के लिए दिया जाता है।

हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत

प्रधानमंत्री मोदी रविवार को अपनी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर स्वीडन के गुटेनबर्ग हवाई अड्डे पहुंचे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने खुद हवाई अड्डे पर मौजूद रहकर मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच होने वाली बैठकों से उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और आर्थिक सहयोग और अधिक प्रगाढ़ होगा।

लू की तपिश से दो दिन झुलसेगी दिल्ली, सहना पड़ेगा 45 डिग्री टॉर्चर, यलो अलर्ट

नई दिल्ली । राजधानी में गर्मी की तपिश के बीच अब लू का सितम भी राजधानीवासियों को झेलना पड़ेगा। मौसम विभाग ने 18 से 23 मई के बीच मौसम गर्म और शुष्क रहने के आसार जताने के साथ ही अधिकतम तापमान के 42 से 45 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। 19 और 20 मई के लिए लू का यलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग के एक वैज्ञानिक ने बताया कि इस अवधि में लगातार तेज और गर्म हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति सामान्य तौर पर 10 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। मौसम शुष्क बने रहने के चलते लगातार तापमान में इजाफा होगा और लोगों को सूरज की तेज तपिश महसूस होगी। लू के रूप में चलने वाली गर्म हवाएं सड़क पर चलने वाले राहगीरों की परेशानी बढ़ाएंगी। रविवार को अधिकतम तापमान 41.9 और न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री दर्ज हुआ। बीते दो दिन से पारा 40 के ऊपर बना हुआ है।

मध्यम श्रेणी में हवा बरकरार

दिल्ली में हवा की दिशा बदलने से फिजा मध्यम श्रेणी में बरकरार है। ऐसे में रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 174 दर्ज किया गया। यह हवा की मध्यम श्रेणी है। इसमें शनिवार की तुलना में दो सूचकांक की गिरावट दर्ज की गई। दूसरी ओर, एनसीआर में ग्रेटर नोएडा की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही। यहां एक्यूआई 260 दर्ज किया गया, यह हवा की खराब श्रेणी है। वहीं, गाजियाबाद में 205, फरीदाबाद में 183 और नोएडा में 175 एक्यूआई दर्ज किया गया। इसके अलावा, गुरुग्राम की हवा सबसे साफ रही। यहां सूचकांक 172 दर्ज किया गया। यह हवा की मध्यम श्रेणी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, हवा पश्चिम दिशा से 20 किलोमीटर प्रतिघंटे के गति से चली। वहीं, अनुमानित अधिकतम मिश्रण गहराई 4500 मीटर रही। इसके अलावा, वेंटिलेशन इंडेक्स 30000 मीटर प्रति वर्ग सेकंड रहा। दूसरी ओर, दोपहर तीन बजे हवा में पीएम10 की मात्रा 190.8 और पीएम2.5 की मात्रा 65 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई। ऐसे में सीपीसीबी का पूर्वानुमान है कि सोमवार से हवा खराब श्रेणी में पहुंच सकती है।

आज होगी वीडी सतीशन की ताजपोशी, खरगे-राहुल गांधी भी होंगे शामिल

नई दिल्ली।

केरल में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस समारोह में शामिल होंगे। पार्टी सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि वायनाड सांसद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी इस समारोह में शामिल होंगी। हालांकि, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी समारोह में शामिल होंगी या नहीं। सतीशन ने पहले कहा था कि पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इस समारोह के लिए दूसरे राज्यों के नेताओं को भी आमंत्रित करेगा। कांग्रेस शासित राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल होंगे। पार्टी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को भी निमंत्रण भेजा है। लेकिन उनकी ओर से अभी पुष्टि का इंतजार है। पार्टी नेताओं ने बताया कि सतीशन अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे। यह समारोह सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में शुरू होगा। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने केरल विधानसभा चुनाव में 140 में से 102 सीटों पर जीत हासिल की।

आज दिल्ली में पहला मेट्रो मंडे, बुधवार-शनिवार वर्क फ्रॉम होम; मंत्री-एमएलए-अधिकारी करेंगे पालन

नई दिल्ली ।

सरकारी कर्मचारियों के लिए सोमवार को पहला मेट्रो मंडे है। दिल्ली सरकार के रविवार देर शाम जारी निर्देश के मुताबिक सभी मंत्रियों, विधायकों और सरकारी अधिकारियों को सोमवार को मेट्रो से सफर करने की सलाह दी गई है।

बुधवार और शनिवार को वर्क फ्रॉम होम रहेगा।

प्रधानमंत्री की ईंधन बचाने की अपील के बाद, दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम और हर सोमवार को मेट्रो मंडे का पालन करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, सड़कों पर जाम कम करने के लिए दिल्ली सरकार और निगम के दफ्तरों के समय में भी बदलाव कर दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य न केवल ईंधन की बचत करना है, बल्कि दिल्ली को प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाना भी है। ईंधन बचाने के लिए, सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल कोटे में 20 फीसदी तक की कटौती की गई है। सरकार ने अपने संसाधनों के इस्तेमाल पर भी कैंची चलाई है। दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी स्टाफ कारों के औसत पेट्रोल उपभोग में कम से कम 20 प्रतिशत की कमी लाएं। इसके साथ ही, सरकारी कर्मचारियों और अन्य दिल्लीवासियों को सलाह दी गई है कि वे कार पूलिंग अपनाएं और सप्ताह में एक दिन स्वेच्छा से नो व्हीकल डे मनाएं।

सरकार चाहती है आप पढ़ो मत, पढ़ेंगे तो नौकरी मांगने लगेंगे; नीट पेपर लीक पर बोले स्वामी अनिरुद्धाचार्य

नेशनल डेस्क।

उत्तर प्रदेश के मथुरा-वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर एक बड़ा और विवादित बयान दिया है। स्वामी जी ने इस पूरे प्रकरण को सरकार की नीयत से जोड़ते हुए कड़ी आलोचना की है, जिससे अब राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है।

नौकरी के डर से शिक्षा नहीं चाहती सरकार

एक कथा के दौरान जब एक श्रद्धालु ने पेपर लीक और छात्रों की बदहाली पर सवाल किया, तो स्वामी अनिरुद्धाचार्य ने दो टूक अंदाज में कहा, सरकार चाहती है कि आप पढ़ो मत।

क्योंकि, आप पढ़-लिख जाएंगे तो नौकरी मांगने लग जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा यह है कि युवा बिना पढ़े-लिखे रहें और महीने का 1000-5000 रुपये लेकर ही खुश रहें।

एग्जाम कैंसिल और बढ़ती उम्र पर तंज

स्वामी जी ने वर्तमान व्यवस्था पर तंज कसते हुए कहा कि आज के समय में छात्र पढ़ाई करते हैं और परीक्षा देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और एग्जाम कैंसिल कर दिया गया।

उन्होंने चिंता जताते हुए कहा, अब पता नहीं अगला एग्जाम कब होगा? तब तक युवाओं की उम्र निकल चुकी होगी। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को देश का एक बड़ा घोटाला करार दिया।

भक्त ने उठाया था सुसाइड और मेहनत का मुद्दा

दरअसल, यह बयान एक भक्त के उस सवाल के जवाब में आया जिसमें नीट परीक्षा रद्द होने के कारण लाखों युवाओं की परेशानी और कुछ छात्रों द्वारा आत्महत्या किए जाने का जिक्र किया गया था। भक्त ने कहा था कि छात्रों ने बड़ी मेहनत की और पैसा खर्च किया, लेकिन पेपर लीक होने से वास्तविक काबिल छात्रों का भारी नुकसान हुआ है, जिस पर सरकार को तत्काल कड़ा एक्शन लेना चाहिए।

स्वामी अनिरुद्धाचार्य के इस बयान के बाद नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच असंतोष का माहौल और गहरा गया है, जबकि विपक्षी दल भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में जुटे हैं।

होर्मुज पार कर एक और एलपीजी टैंकर पहुंचा भारत

तेल अवीव । ईरान जंग के बीच एक और एलपीजी टैंकर होर्मुज पार कर भारत पहुंच गया है। मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला टैंकर 'सिमी' 20 हजार टन एलपीजी लेकर गुजरात के कांडला पोर्ट पहुंचा। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक, जंग शुरू होने के बाद अब तक 15 एलपीजी जहाज भारत पहुंच चुके हैं। टैंकर 'सिमी' ने 13 मई को होर्मुज स्ट्रेट पार किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत आने वाला एलपीजी जहाज MV सनशाइन' भी हाल ही में सुरक्षित तरीके से होर्मुज पार कर चुका है। जहाजों की सुरक्षित आवाजाही में भारतीय नौसेना समेत कई एजेंसियां मदद कर रही हैं।

देश को एक वैचारिक राष्ट्र में बदलने की हो रही कोशिश- अरशद मदनी बोले- मुसलमान न कभी झुका है और न कभी झुकेगा

नई दिल्ली। जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा है कि देश को योजनाबद्ध तरीके से एक वैचारिक राष्ट्र में बदलने की कोशिश की जा रही है। मदनी ने कहा कि पहले केवल मुसलमान निशाने पर थे। अब इस्लाम को भी निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमान न कभी झुका है और न कभी झुकेगा। अरशद मदनी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जमीयत उलमा-ए-हिंद की कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक का घोषणापत्र जारी किया। मदनी ने कहा, देश के वर्तमान हालात, बढ़ती सांप्रदायिकता, संवैधानिक संस्थाओं की चुप्पी,

> **"अरशद मदनी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, देश में नफरत की राजनीति अब धमकी की राजनीति में बदल चुकी है, जिसका उद्देश्य मुसलमानों को भयभीत करके उन्हें अपनी शर्तों पर जीवन बिताने के लिए मजबूर करना है।**

मुसलमानों और इस्लामी प्रतीकों के खिलाफ कड़े कदम तथा नफरत आधारित राजनीति अत्यंत चिंताजनक है। हालांकि मुसलमान न कभी झुका है और न कभी झुकेगा। वह प्रेम से झुक सकता है, लेकिन ताकत, धमकी और अत्याचार के सामने उसे कभी झुकाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा- सत्ता प्राप्ति के लिए अमन और एकता के साथ खतरनाक खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप धार्मिक उन्माद और नफरत लगातार बढ़ रही है, जबकि कानून के रखवाले मूकदर्शक बने हुए हैं। हालिया चुनावों के बाद कुछ राजनीतिज्ञों में नफरत के आधार पर सत्ता हासिल करने का चलन और बढ़ गई है। बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यकों के विरुद्ध खड़ा करने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, जबकि सरकारें भय और धमकी से नहीं बल्कि न्याय और इंसाफ से चलती हैं। अरशद मदनी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बयान का जिक्र किया। मदनी ने कहा, पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का यह बयान कि वे सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के पूरी तरह विरुद्ध है, क्योंकि हर मुख्यमंत्री शपथ लेकर सभी नागरिकों के साथ न्याय करने का संकल्प लेता है। सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी हर नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है, न कि किसी विशेष वर्ग के खिलाफ नफरत और विभाजन की राजनीति करना। इसके साथ ही, मदनी ने एक्स पोस्ट में कहा, देश को योजनाबद्ध तरीके से एक वैचारिक राष्ट्र में बदलने की कोशिश की जा रही है। समान नागरिक संहिता, वंदे मातरम को अनिवार्य बनाना, मस्जिदों और मदरसों के खिलाफ कार्रवाइयां व एसआईआर की आड़ में वास्तविक नागरिकों को मताधिकार से वंचित करने जैसे कदम इसी सिलसिले की कड़ियां हैं। मदनी ने कहा कि जमीयत उलमा-ए-हिंद इन सभी कदमों के खिलाफ अपनी कानूनी और लोकतांत्रिक लड़ाई जारी रखेगी। मदनी ने यह भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी मुसलमानों को सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया, लेकिन आज हालात उससे कहीं अधिक गंभीर हो चुके हैं। पहले केवल मुसलमान निशाने पर थे। अब इस्लाम को भी निशाना बनाया जा रहा है। अरशद मदनी ने कहा, वर्ष 2014 के बाद बनाए गए कानूनों और हालिया कदमों इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वर्तमान सरकार केवल मुसलमानों ही नहीं, बल्कि इस्लाम को भी नुकसान पहुंचाना चाहती है।

जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने अपने पोस्ट के आखिर में लिखा, हम सभी न्यायप्रिय दलों, सामाजिक संगठनों और देशहित में सोचने वाले नागरिकों से अपील करते हैं कि वे एकजुट होकर सांप्रदायिक और फासीवादी ताकतों का लोकतांत्रिक और सामाजिक स्तर पर मुकाबला करें व देश में भाईचारा, सहिष्णुता, न्याय और संविधान की सर्वोच्चता के लिए संयुक्त संघर्ष करें।